



## पीएम मोदी ने महिलाओं को दिया बीमा सखी योजना का बड़ा तोहफा नारी शक्ति की अब बदल जाएगी तकदीर

- एलआईसी की बीमा सखी योजना का किया उद्घाटन
- दो लाख महिलाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर



**पानीपत।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरियाणा के पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 'बीमा सखी' योजना का उद्घाटन किया।

इस मौके पर उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। बीमा सखी योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार प्रदान करना और उन्हें बीमा क्षेत्र में सशक्त बनाना है।

इस योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। बीमा सखी ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा जागरूकता बढ़ाने के साथ बीमा सेवाएं प्रदान करेगी। यह योजना महिलाओं को आय अर्जित करने का जरिया भी नहीं, बल्कि उनके आत्मनिर्भरता के सपने को भी साकार करेगी। पीएम ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 10 करोड़ महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने में भूमिका निभा रही हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा के नारी सशक्तिकरण मॉडल की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम पूरे देश में देखने को मिले। उन्होंने कहा कि पानीपत एक बार फिर नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि महिलाओं के लिए भाजपा सरकार ने कई नई राहें खोली हैं। इसकी वजह से आज महिलाएं सेना की अग्रिम पंक्तियों में तैनात की जा रही हैं। फाइटर पायलट और पुलिस भर्ती में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

### महिला सशक्तिकरण पर पीएम का संदेश

महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी ऊर्जा है। हमारी महिलाएं विकसित भारत का आधार बनेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब महिलाओं को अवसर दिया जाता है, तो वे देश के विकास के लिए नए रास्ते खोलती हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जनधन खातों के जरिए 30 करोड़ महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ा गया। आज महिलाएं बैंक सखी, कृषि सखी, और पशु सखी जैसे पहलुओं में नेतृत्व कर रही हैं।

साथ ही 1,200 दुग्ध उत्पादक संघ महिलाओं के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य में महिलाओं को भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं केवल परिवार और समाज की शक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख आधारशिला हैं।

## देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सदन में हासिल किया विश्वास मत

- राहुल नावेंकर विरोध चुने गए अध्यक्ष



**मुंबई।** देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। शिवसेना विधायक उदय सामंत और अन्य द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर को एक बार फिर विधान अध्यक्ष चुन लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने घोषणा की कि सदन ने विश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 'महायुति' गठबंधन के पास 288 संसदीय राज्य विधानसभा में 230 सीटों का बहुमत है। नावेंकर ने विधानसभा में कहा, 'विश्वास मत बहुमत से पारित हो गया है।'

विधानसभा की कार्यवाही अब स्थगित की जाती है और आज महाराष्ट्र के राज्यालय के अधिभाषण के बाद फिर से शुरू होगी। पांच दिसंबर को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदगी में आयोजित समारोह में फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर सात दिसंबर को शुरू हुआ। 288 सदस्यीय निचले सदन में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 230 सीटें हासिल कीं, इसलिए बहुमत साबित करना महज औपचारिकता थी। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री उदय सामंत, भाजपा विधायक संजय कुटे, वरिष्ठ राकांपा नेता और पूर्व मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और निर्दलीय विधायक रवि राणा ने निचले सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया।

### न्यूज डायरी

**नौ जिलों में हटा इंटरनेट बैन**  
इंफाल। मणिपुर सरकार ने चुराचांदपुर और थोबल सहित नौ जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन को वापस ले लिया। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। आद्युक्त (गृह) एन अशोक कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति और इंटरनेट सेवाओं के सामाज्य संचालन के साथ इसके संभावित सह-संबंध की समीक्षा करने के बाद सभी प्रकार के अस्थायी निलंबन को हटाने का फैसला किया है।

### 14 को जवाब देगे पीएम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली।

भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर को बहस का जवाब देंगे। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को बहस होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को उच्च सदन में चर्चा का नेतृत्व करेंगे। संसदीय गतिरोध का अंत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला द्वारा पिछले सप्ताह एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता के बाद हुआ।

### अविश्वास प्रस्ताव लागू विपक्ष नई दिल्ली।

संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को 10वां दिन रहा। बांग्लादेश हिंसा समेत तमाम मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के नेतृत्व में तैयार किए गए इस प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी (सपा) और तृणमूल कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यशैली और फैसलों को लेकर विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और राजीव शुक्ला जैसे वरिष्ठ नेताओं ने सभापति पर पदापात का आरोप लगाया।

## धार्मिक स्थलों और हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं : विक्रम मिसरी

- ढाका में भारत के विदेश सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक
- बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण पर हुई चर्चा

**ढाका।** भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी सोमवार को बांग्लादेश के दौरे पर आए। विदेश सचिव ने यहां मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ व्यापक वार्ता की। जिसमें उन्होंने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता जताई। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि हमने हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और मैंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से भी अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों पर हमलों की चिंताजनक घटनाओं पर भी चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और परस्परिक रूप से लाभकारी संबंध चाहता है। मैंने आज बांग्लादेश प्राधिकरण की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा को रेखांकित किया है। उन्होंने बांग्लादेश के विदेश सचिव जशीमुद्दीन के साथ व्यापार, वीजा पॉलिसी, सीमा पर तनाव, जल-बंटवारा और आपसी हित समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

### केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की गवर्नर की नियुक्ति पर मुहर

**नई दिल्ली।** राजस्थान कैबिनेट कमेटी ने भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त कर दिया है। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैबिनेट के आईएसएस होने के साथ राजस्थान के ही रहने वाले भी हैं। उनका होम टाउन बिकानेर है। राजस्थान से वे जनवरी 2020 में प्रतिनिधिक पद के केंद्र में चले गए थे। यहां पहले उर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनाती मिली।

**राज के पसंदीदा अफसर रहे**  
जब 1999 में राजस्थान से तत्कालीन सांसद वसुंधरा राजे को वाजपेयी मंत्रिमंडल में जगह मिली तो उन्होंने इस डायनेमिक अधिकारी को दिल्ली बुलाकर अपने मंत्रालय में कार्यभार दिया। वर्ष 2003 में संजय मल्होत्रा को संयुक्त राष्ट्र डेवेलपमेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया।

## किसान किसी के सामने हाथ न फैलाएं: योगी

### 'कृषिका- खेती से समृद्धि की ओर' कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- मुख्यमंत्री ने 11 किसानों को किया सम्मानित
- 14 लाख से अधिक किसानों के निजी ट्यूबवेल की बिजली माफ



**लखनऊ।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद किसानों के नाम पर राजनीति बहुत लोगों ने की, लेकिन किसान राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सके, 2014 में ईमानदारी से यह प्रयास पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने मुदा परीक्षण कार्ड जारी किया। पीएम कृषि बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई जैसी योजनाएं चलाई गईं। यूपी में सात वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त

सुविधा देकर किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाया गया। 2021 में पीएम ने बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। इसके पहले यहां किसानों को प्रति बीघा पांच हजार रुपये सालाना मिलता था, लेकिन लोकार्पण के दो वर्ष बाद वहां के किसानों ने बताया कि उन लोगों ने उन्हीं क्षेत्रों में प्रति बीघा 50 हजार रुपये की आमदनी

मिला। अनदाता किसानों को हाथ न फैलाना पड़े। इस उद्देश्य से देश में 12 करोड़ और यूपी में 2.62 करोड़ कृषकों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक समाचार पत्र समूह की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'कृषिका-खेती से समृद्धि की ओर' कार्यक्रम में सोमवार को अपनी बातें रखीं। सीएम ने समाचार पत्र के रचनात्मक कार्यक्रमों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने 11 किसानों को चेक, अंशवस्त्र व स्मृति चिह्न प्रदान किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत पहले से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में आज भी लगभग 30 फीसदी शहरीकरणों को छोड़ दें तो 70 फीसदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है।

## धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

### याचिका

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही, जिसमें बंगाल में 2010 से कई जातियों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट के 22 मई के फैसले को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका सहित सभी याचिकाएं जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। जस्टिस गवई ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ

### बंगाल के ओबीसी मानले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने की टिप्पणी

अधिवाक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह धर्म के आधार पर नहीं है। यह पिछड़ेपन के आधार पर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सात जनवरी को विस्तृत दलीलों सुनेगी। बता दें कि हाई कोर्ट ने बंगाल में 2010 से कई जातियों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया था और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए आरक्षण को अवैध ठहराया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि वास्तव में इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत हो रहा है।

### संसद सत्र संसद परिसर में कांग्रेस के सांसदों ने किया प्रदर्शन

## अदाणी मुद्दे पर आक्रामक कांग्रेस बैकफुट पर दिखी

- अदाणी मुद्दे पर नहीं मिला सपा व टीएमसी का साथ
- जार्ज सोरोस व कांग्रेस के संबंधों पर संसद में हंगामा



**नई दिल्ली।** संसद के दोनों सदन में सोमवार को अमेरिकी कारोबारी जार्ज सोरोस और कांग्रेस के साथ संबंधों को लेकर सामने आए नए गठजोड़ को लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। साथ ही दोनों सदन में देश की संप्रभुता और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। हालांकि इस मांग का कांग्रेस ने विरोध किया और कहा कि अदाणी मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष यह झूठ फैला रहा है। राज्यसभा में इस मुद्दे पर सबसे अधिक हंगामा हुआ। वहीं अब तक हंगामे आगे दिखने वाली कांग्रेस इस दौरान बैकफुट पर दिखी। उसके नेता

शिवसेना-यूटोवी उसके साथ खड़ी दिखी। कांग्रेसी सांसदों ने इस दौरान संसद परिसर के बाहर राहुल गांधी की अनुवायि में विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने इस बीच सभापति पर भेदभाव का आरोप लगाया है। भाजपा की ओर से जैसे ही जार्ज सोरोस और कांग्रेस का मुद्दा उठाया गया वैसे ही कांग्रेस ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

साथ राहुल गांधी को देशद्रोही कहे जाने पर माफ़ी के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। हालांकि दोनों ही सदन में कांग्रेस को इस मुद्दे पर टीएमसी और सपा जैसे विपक्षी दलों का साथ नहीं मिला। सदन के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस के इस रवैी की तीखी आलोचना की और कहा कि जब विषय अनुकूल तो हंगामा जब विषय प्रतिकूल तो सदन चलाने की मांग की है।

### श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर जनवरी तक टली सुनवाई

**नई दिल्ली।** मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही इंदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के सीधे सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने पर मंदिर पक्ष के एक पक्षकार ने सोमवार को आपत्ति उठाई। कहा कि एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की ही खंडपीठ में अपील दाखिल करनी चाहिए थी। मंदिर पक्ष की ओर से बहस अभी जारी है और अब मामले में अगली सुनवाई सदी की छुट्टियों के बाद जनवरी में होगी। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट की एकलपीठ ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही इंदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े 15 मूल मुकदमों को सुनवाई योग्य माना था। उन मुकदमों में मंदिर पक्ष की ओर से शाही इंदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मस्थान बताते हुए दावा किया गया है।

### एक देश-एक चुनाव संसद सत्र में विधेयक पेश कर सकती है सरकार

**नई दिल्ली।** केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसी संसद सत्र में एक देश-एक चुनाव विधेयक पेश किया जा सकता है। विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की बात भी कही जा रही है। गौरतलब है कि एक देश, एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले एक देश एक चुनाव प्रस्ताव का उद्देश्य देश में एक साथ चुनाव कराना है, जिससे संसाधन, समय और लागत की बचत होगी। अभी राज्यों में अलग-अलग और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। यह एक बड़ी पहल है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि केंद्र

की इस पहल को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे साफ है कि केंद्र सरकार को इस विधेयक पर आम सहमति बनाने में सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों में सहमति बनाने के लिए केंद्र सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज सकती है। एक देश एक चुनाव को हकीकत में बदलने के लिए सरकार को संविधान में भी संशोधन करना होगा, जिसके लिए यह विधेयक दोनों सदन के दो तिहाई बहुमत से पास होने जरूरी है।



























